

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2762
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

मत्स्ययन हिम संयंत्र

2762. श्री हमदुल्ला सईद :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास स्थानीय मछुआरा समुदाय की सहायता करने के लिए लक्षद्वीप के चेतलाट, किल्टन और वित्रा द्वीपों में कंटेनर प्रकार के हिम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो प्रशासनिक अनुमोदन, स्थल चयन, अनुमानित लागत और पूरा होने की समय-सीमा सहित इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा इन हिम संयंत्रों के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, अनुरक्षण और प्रचालनात्मक सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार ने मछलियों के संरक्षण, आय सृजन और मछुआरों की आजीविका पर ऐसे संयंत्र के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा उक्त द्वीपों में इन सुविधाओं की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) से (ङ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने चार आइस प्लांट यूनिटों सहित अनेक मात्स्यिकी संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 44.20 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ कुल 62.43 करोड़ रुपए की लागत पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि चेतलाट, किल्टन या बिट्रा में कंटेनेराइज़्ड आइस प्लांट्स के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। बिट्रा में पहले से ही 5 टन/प्रति दिन का ब्लॉक आइस प्लांट परिचालन में है। इसके अलावा, PMMSY के अंतर्गत चेतलाट और किल्टन के लिए 5 टन/प्रति दिन डायरेक्ट एक्सपेंशन (DX) ब्लॉक आइस प्लांट स्वीकृत किए गए हैं और प्रत्येक को 68.44 लाख का आवंटन दिया गया है तथा खरीद निविदाएं जारी की गई हैं। इन सुविधाओं के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की डीजल आधारित उत्पादन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हालांकि मत्स्य संरक्षण या मछुआरों की आजीविका पर आइस प्लांट्स के विशिष्ट प्रभाव पर कोई अलग सरकारी अध्ययन नहीं किया गया है, PMMSY के अंतर्गत व्यापक क्षेत्रीय सुधार सकारात्मक परिणाम दर्शाते हैं। लक्षद्वीप में मत्स्य उत्पादन 1960 के दशक में लगभग 500 टन से बढ़कर हाल के वर्षों में सालाना लगभग 20,000 टन हो गया है। ये रुझान दर्शाते हैं कि संरक्षण और प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार ने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया है, जिससे मछुआरा समुदायों के लिए उच्च आय और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।